

न्यूज डायरी

लालू 13वीं बार बने अध्यक्ष पांच को होगी ताजपोशी

पटना। लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 5 जुलाई को लालू यादव की राजद के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी। इस पद के लिए सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने ही नामांकन दाखिल किया था। पटना में मंगलवार को पखऊके राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वी ने लालू के चुने जाने का ऐलान किया।

सिमडेगा में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत

सिमडेगा। कोलेबिरा-पालकोट सीमा पर स्थित जामटोली गांव के पास एक तेज रफतार ट्रेलर ने बाइक पर सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गयी। मृतकों की पहचान अमित बघवार, सोनू बघवार और मनु खड़िया के रूप में हुई। तीनों युवक एक ही बाइक से कोलेबिरा जा रहे थे। सामने से आ रहे एक ट्रेलर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौत

गिरिडीह। सरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना बाइक सवार दामाद और ससुर की मौत हो गयी। दामाद गौरव कुमार अपने ससुर सहदेव मंडल को ले कर बगोदर जा रहे थे। बगोदर-सरिया अनुमंडल दपतर के पास खड़े ट्रक से बाइक की जोरदार टक्कर हो गयी। दोनों की एक साथ मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

सीएम हेमंत ने नयी दिल्ली में झारखंड भवन का किया निरीक्षण

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को नयी दिल्ली प्रवास के दौरान नवनिर्मित झारखंड भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में मौजूद अधिकारियों को से व्यवस्थाओं से संबंधित कई दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि झारखंड भवन में सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाये।



गंगाराम अस्पताल में गुरुजी से मिले हेमंत

सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में बीमार पिता शिबू सोरेन से मिले और उनका हालचाल लिया। पिता की सेहत को लेकर डाक्टरों से भी बातचीत की। गुरुजी स्वस्थ कारणों से अस्पताल में भर्ती हैं।



संघर्ष विराम के उलंघन का जवाब देने की चेतावनी दी

इजराइल ईरान के साथ संघर्ष विराम पर सहमत

एजेंसी

तेल अवीव। इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तेहरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को समाप्त करने के खतरे के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद युद्ध विराम पर सहमति जतायी। उन्होंने अमरीका को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध विराम उल्लंघन का इजराइल जोरदार तरीके से जवाब देगा।

मंगलवार की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि इजराइल



इजराइल ने लगाया आरोप ईरान ने युद्ध विराम तोड़ा

तेल अवीव। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। रक्षामंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि इसका ईरान को करारा जवाब दिया जायेगा। उन्होंने अपने डिफेंस फोर्सज को तेहरान को जोरदार जवाब देने का निर्देश दिया है। हालांकि ईरान ने किसी हमले से इनकार किया है। संघर्ष विराम टूटने पर ट्रंप का गुस्सा फूटा। उन्होंने दोनों को हड़काया और समझौते का पालन करने को कहा।

अनिश्चितता बनी हुई है। पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है।

पीएम ने कहा- मेड इन इंडिया हथियार प्रभावशाली

अब आतंकियों का कहीं भी कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं

एजेंसी

नयी दिल्ली। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब कठोर और निर्णायक नीति अपना चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान मेड इन इंडिया हथियारों का उपयोग करते हुए केवल 22 मिनट में दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि मेड इन इंडिया हथियार कितने प्रभावशाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये हथियार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होंगे। पीएम ने कहा, हमने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के निर्दोष नागरिकों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए अब कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है।



पीएम मोदी ने उक्त बातें श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति दुनिया के सामने रखी। भारत कभी भी अपने नागरिकों का खून बहानेवालों को छोड़ेगा नहीं। **आत्मनिर्भर भारत** : पीएम ने कहा कि भारत अब रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। देश ने बीते 11 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को मजबूती देने की दिशा में तेजी से काम किया है।

रेल किराये में एक जुलाई से होगी मामूली बढ़ोतरी

लोकल ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। मंथली सीजन टिकट के दाम पहले जैसे ही रहेंगे।

साधारण दूसरी क्लास में 500 किलोमीटर तक के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

साधारण दूसरी क्लास में 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किराया आधा पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा।

मेल और एक्सप्रेस (नॉन-एसी) ट्रेनों में किराया 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा।

एसी क्लास में किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा।



रेलवे का फैसला

एजेंसी

नयी दिल्ली। रेल मंत्रालय ने अगले महीने की शुरुआत से ट्रेन टिकटों के दाम में मामूली बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। हालांकि लोकल ट्रेन और मंथली सीजन टिकट या एमएसटी के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।

रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, साधारण मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों (नॉन-एसी) का किराया एक पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा जबकि एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। किराए में यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 से होगी। सूत्रों ने बताया कि लोकल ट्रेनों और 500 किलोमीटर तक की जनरल या सेकेंड क्लास की यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के किराये में आधा पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा।

तत्काल टिकटों की बुकिंग में भी बदलाव, आधार जरूरी

रेलवे के एक और बड़े फैसले में तत्काल टिकटों की बुकिंग से है। एक जुलाई, 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। मंत्रालय ने जारी सूचना में कहा है कि इसका मकसद तत्काल योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना है।

ओटीपी भी जरूरी : मंत्रालय ने बताया है कि 15 जुलाई, 2025 से तत्काल टिकट बुक करते समय यात्रियों को आधार कार्ड से ओटीपी के जरिए भी वेरिफाई करना होगा। यह एक और जरूरी कदम होगा। अब IRCTC के एजेंट पहले आधे घंटे तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। एसी क्लास के लिए ये नियम सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे तक और नॉन-एसी क्लास के लिए सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगा। मतलब, एजेंट इन समयों पर तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

अपनी नसों में नशा नहीं जिंदगी को दौड़ने दीजिये

मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता हेतु युवाओं द्वारा मैराथन दौड़

मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक

दिनांक: 26 जून 2025

समय: सुबह 6:00 बजे

आप सभी इस मैराथन दौड़ में सादर आमंत्रित हैं

बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी रांची

रेडियम रोड

कचहरी चौक

अल्बर्ट एक्का चौक

नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के उद्देश्य से ई-शपथ कार्यक्रम

नशा के विरुद्ध ई-शपथ ऐसे लें

GO TO WEBSITE

http://nmba.dosje.gov.in

Join Nasha Mukht Bharat Abhiyaan! Take e-pledge today! 183686

TAKE PLEDGE

ENTER BASIC DETAILS

SUBMIT

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

PRNO 355886 (IPRD) 25-26



पत्रकार अरुण रंजन का निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति : सरयू



रांची। जदयू विधायक सरयू राय ने वरिष्ठ पत्रकार अरुण रंजन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत क्षति है। अरुण रंजन जो से मेरा घनिष्ठ संबंध 1974 के जेपी आंदोलन के समय से रहा है। इसका निर्वाह उनके अंतिम दिनों तक होता रहा। पश्चिम पत्रिका रविवार और दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स में उनकी पत्रकारिता के साथ मैं गहराई से जुड़ा रहा। एक मेधावी, मेहनती, दूरदर्शी पत्रकार के नाते अरुण जी की स्मृति स्थायी रहेगी। मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। ईश्वर पुण्यात्मा को सद्गति प्रदान करें।



खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण को

लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद थे।

इस क्रम में रांची की हिंदपीढ़ी निवासी एक महिला फरियाद लेकर मंत्री के जनता दरबार में पहुंचीं। महिला ने बताया कि उसका पति

जनता दरबार कांग्रेस की बेहतरीन पहल : दीपिका

जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हमारे समक्ष कई मामले सामने आए हैं। कई प्रखंडों में वर्षों से जमे पदाधिकारी के तबादले, सड़क निर्माण, चिकित्सा के अलावे अन्य मामले भी सामने आए हैं। ग्रामीण विकास से सड़क निर्माण का मामला भी आया है जिस पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन सड़क निर्माण की प्रक्रिया में समय लगता है। जनता दरबार कांग्रेस की ओर से यह एक बेहतरीन पहल है जिसमें जनता हमसे संवाद कर अपनी बातों

को रखती है, हम हर समस्या के समाधान के लिए सजग हैं, हमारा प्रयास है कि जो सामान्य प्रक्रिया के तहत दूर होने वाली समस्याएं हैं वह तुरंत दूर हो। कई समस्याओं पर विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। जिन मुद्दों पर ज्यादा फॉलोअप कि आवश्यकता होगी उसे विभागीय स्तर पर करके प्रदेश कार्यालय को सूचित किया जाएगा। वहीं प्रत्येक आवेदनकर्ता को समस्या का समाधान होने के बाद सूचित किया जाएगा।

महिला ने बताया कि उसकी शादी कश्मीर के युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद पारिवारिक तनाव इस कदर बढ़ा कि हिंदपीढ़ी में महिला को छोड़कर उसका पति बच्ची को लेकर कश्मीर चला गया। मंत्री

दीपिका पांडे सिंह के समक्ष महिला द्वारा लिखित शिकायत देने के बाद तत्काल रांची एसएसपी को इससे अवगत कराते हुए इस मामले में महिला को सहयोग कराने का निर्देश ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया

जनता दरबार से लोगों को फायदा: सोनाल

इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति कहते हैं कि मंत्रियों के जनता दरबार से लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का जनता दरबार लगा था। जिसमें 97 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी तरह कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिकी के जनता दरबार में 85 आवेदन आए थे। कांग्रेस भवन में प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारी के पास भेज दिया जाता है, जिस पर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी की सोच है कि जनता की छोटी-मोटी समस्या का निराकरण त्वरित गति से हो और इस संबंध में जो कुछ भी बाधाएं आती हैं उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सभी चारों मंत्रियों के द्वारा जनता दरबार लगाया गया था। उसकी सफलता के बाद दूसरे चरण में मंत्रियों के द्वारा इन दिनों जनता की समस्या कांग्रेस भवन में सुनी जा रही है। अब तक तीन मंत्रियों का इस तरह का जनता दरबार लग चुका है। आने वाले समय में शेष बचे एक मंत्री का भी जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार में कमल ठाकुर, अभिलाष साहू, राजन वर्मा, नरेंद्र लाल गोपी, राजीव चौधरी अजय जैन, प्रशांत पांडे भी उपस्थित थे।

है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मामले को पूरी तरह से पारिवारिक विवाद बताते हुए बच्ची को मां के पास लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक बच्ची को मां से दूर नहीं किया जा सकता है।

जनता दरबार में 63 मामले सामने आये : जनता दरबार में कुल 66 मामले सामने आए। जिसमें विभागीय शिकायतों के साथ-साथ अन्य विभागों के मामले देखे गए।

जनसमस्याओं को लेकर भाजपा ने 264 प्रखंडों में किया आक्रोश प्रदर्शन

भ्रष्ट हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें कार्यकर्ता : बाबूलाल मरांडी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। भाजपा ने मंगलवार को गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, पेसा कानून, आर्कट भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था के मुद्दों पर सभी अंचलों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार लूट बंद करे, अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतारे नहीं तो आक्रोश प्रदर्शन तेज होगा। उन्होंने गिरिडीह जिलांतर्गत तीसरी और गावां प्रखंड कार्यालय में आक्रोश प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने हेमंत सरकार की नाकामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी, दलित, महिला, किसान, युवा विरोधी सरकार है। हेमंत सरकार पार्ट 2 भी उसी तर्ज पर चल रही जैसा पिछले पांच वर्षों में चली। इसके नीयत और नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आज दलाल, बिचौलिये राज्य के खान खनिज को लूट



रहे हैं लेकिन, गांव में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास एअरुआ आवास बनाने केलिये बालू नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि माफिया लोग गांव से नदी के बालू को बाहर ले जा रहे और स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर को पुलिस पकड़कर मुकदमा करती है। उन्होंने कहा कि आवास की योजना में पदाधिकारी 25 हजार तक कमीशन ले रहे और बालू भी गरीबों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों को यह सरकार चारों तरफ से परेशान कर रही है। जमीन के कागजात बिना पैसे के नहीं बन रहे हैं। इसके कारण गरीबों के जमीन और अवैध कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड के अस्पतालों में डॉक्टरों नहीं एम्बुलेंस

नहीं, दवाई नहीं। मजबूरी में गरीब जिला मुख्यालय या फिर रांची राजधानी के अस्पतालों में जाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा हलाश और निराश ले जा रहे और स्थानीय लोगों को बेच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में इंटर की पढ़ाई को विश्वविद्यालय की शिक्षा से बाहर कर दिया है लेकिन, राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों से इंटर कॉलेज की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया। आज लाखों छात्र इंटर में नामांकन केलिये चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फिर एक बार धान की खरीदारी में किसानों को परेशान किया है। 3200 रुप प्रति क्विंटल खरीद की घोषणा करने वाली

सरकार किसानों से 2400 रुपये क्विंटल धान की खरीदारी की। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो भाजपा बार बार जनता की समस्याओं केलिए आंदोलन करने को मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि थाना ब्लॉक अंचल जिला सभी सरकारी कार्यालयों की स्थिति एक जैसी है। भाजपा ने प्रखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन कर चेतावनी दी हैं।

राज्य सरकार नहीं सुधरती है तो भाजपा थाना, जिला सहित जन मुद्दों से जुड़े अन्य कार्यालयों पर बड़ा प्रदर्शन और उसे ठप कराने को मजबूर होंगे। पूरे प्रदेश के अलग अलग प्रखंडों में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रवींद्र कुमार राय, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सांसद आदित्य साहू, मनोज कुमार सिंह, अमर कुमार बाउरी, सांसद-विधायक गण, प्रदेश के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की विफलताओं से संबंधित नारे बाजी कीए।जनता को संबोधित किया एवं जापन भी सौंपा।

झारखंड में हर हत्या की जिम्मेदार सरकार : सीपी

रांची। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अंचल कार्यालयों में बिना पैसे दिये कोई काम नहीं होता है। श्री सिंह मंगलवार को अरगोड़ा अंचल के घेराव-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया हैं। रांची में जितनी भी हत्या और आत्महत्या हो रही है उनका जिम्मेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंचलों में होने वाला भ्रष्टाचार है। विधायक नवीन जायसवाल ने भ्रष्ट पदाधिकारी और सरकार को चेतावनी देते हुये कहा कि अगर झारखंड की जनता को परेशान करना नहीं छोड़ा तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरुण साहू, ओम प्रकाश, रौशनी खलको, संजय जयसवाल, राजू सिंह, अनिता वर्मा, अशोक मिश्रा, सुजीत शर्मा, सूर्यप्रताप, विनोद महतो आदि शामिल थे।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणु गोपाल से मिले बंधु तिकी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिकी ने दिल्ली में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज और वित्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बंधु तिकी ने राज्य में प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। मुलाकात के दौरान बंधु तिकी ने नेताओं के समक्ष झारखंड में कांग्रेस का संगठन कैसे प्रभावशाली बने और जनता से जुड़ी समस्याओं का समय रहते ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बताया कि गठबंधन वाली सरकार



की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में संगठन की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की बात कही। इतना ही नहीं राज्य की जनता से किए गए हर वायदे को समय पर धरातल पर उतारने की भी बात कही।

क्या है कांग्रेस का आगामी कार्यक्रम : मुलाकात के दौरान

वर्तमान में राज्य के सभी 24 जिलों में कांग्रेस संगठन को गतिशील बनाने और कार्यकर्ताओं की भूमिका को रेखांकित करने का निर्णय लिया गया है। बंधु तिकी ने कहा कि कांग्रेस फिर एक बार अपने पुराने राजनीतिक इतिहास को रचने के लिए तैयार है। जिसमें संगठन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। भाजपा द्वारा झारखंड के प्रखंडों में किए गए ‘आक्रोश प्रदर्शन’ को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राजनीतिक नोटकी करार दिया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि यह प्रदर्शन न तो जनता के लिए था और न ही जनहित से इसका कोई वास्ता है, बल्कि यह भाजपा की हताशा और बौखलाहट का प्रतीक है। विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा को इस बात का कष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी-मूलवासी सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं सहित हर वर्ग के लिए काम कर रही है। भाजपा जिन सवालियों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वे वही मुद्दे हैं, जिन्हें भाजपा ने

अपनी सत्ता में पूरी तरह नजरअंदाज किया था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बालू नीति, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भाजपा का बोलना हास्यास्पद है, क्योंकि उनके शासनकाल में बालू माफिया सबसे ज्यादा सक्रिय थे, योजनाएं ठप थीं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी और युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमले दिए गए थे। अपने इन्ही कृत्य के कारण भाजपा को प्रदेश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था और इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व को आपार बहुमत देकर सत्ता की बागडोर सौंपी है।

पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा

कि एक समय मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मरांडी जी झारखंड की जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे आज जिन मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हीं समस्याओं की जड़ें भाजपा शासन में पड़ीं।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसमें सच्चाई और नीयत की ईमानदारी होनी चाहिए। विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। पेसा कानून का लागू होना, स्थानीयता पर आधारित नियोजन नीति, महिला सशक्तिकरण, मईयां सम्मान और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिनसे भाजपा घबराई हुई है।

भाकपा माले ने 9 जुलाई की हड़ताल को सफल बनाने का लिया निर्णय

रांची। भाकपा माले ने 9 जुलाई को घोषित देशव्यापी मजदूर विरोधी चार श्रम कोड़ों के खिलाफ हड़ताल को सफल बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मंगलवार को संपन्न हुई दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में पार्टी के सभी जनसंगठनों के सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सितंबर माह तक पार्टी सभी जिला सम्मेलन संपन्न करने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 जुलाई से 28 जुलाई तक जुलाई अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान सदस्यता अभियान को तेज किया जाएगा और ग्रांव कमेटीयों का निर्माण किया जाएगा।

नगर विकास मंत्री सुदित्य कुमार ने केंद्रीय नगर विकास मंत्री को लिखा तीन पन्ने का पत्र तमामी गंगे योजना से गंगा की सहायक नदियों के अलावा अन्य नदियों को भी जोड़ने की मांग

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदित्य कुमार ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। इसमें मंत्री ने लिखा है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान शहरी विकास के क्षेत्र में झारखंड राज्य के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर आकृष्ट करना चाहता हूं, तथा केंद्र सरकार से उचित सहायता के लिए आपके बहुमूल्य हस्तक्षेप का आग्रह करना चाहता हूं। झारखंड का तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा

है, लेकिन शहरी बुनियादी ढांचे, किफायती आवास और संगठित सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं की अत्यधिक कमी है। इसके अतिरिक्त, राज्य में शहरी स्थानीय निकाय का क्षमता संवर्धन किया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। झारखंड राज्य के पृथक सामाजिक-आर्थिक संदर्भ को देखते हुए, मैं आपका ध्यान कुछ विशेष मुद्दों पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

इनमें भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत गंगा एवं उसके सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए योजना स्वीकृत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा एवं उसके बेसिन में अवस्थित नदियों को प्रदूषण मुक्त करना है। गंगा की सहायक नदी दामोदर को स्वच्छ रखने के लिए राज्य के तीन शहरों यथा-धनबाद, फुर्सो एवं रामगढ़ में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन योजना का कार्यान्वयन नमामि गंगे परियोजना के तहत कराया जा रहा है। परंतु इसमें सिवरेज नेटवर्क का



प्रावधान नहीं है। इस कारण इसका पूर्ण लाभ नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना है कि इस परियोजना के साथ गंगा की सहायक नदियों के

अलावा अन्य नदियों को भी जोड़े जाने से इसका दूरगामी प्रभाव होगा। झारखण्ड राज्य में उपरोक्त शहरों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण शहर अन्य नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जिनका प्रदूषित जल प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में प्रवाहित होता है, जैसे-स्वर्णरेखा नदी के किनारे रांची एवं जमशेदपुर, गरमा नदी के किनारे बोकारो (चास), अजय नदी के किनारे देवघर, उसरी नदी के किनारे गिरिडीह, मयुराक्षी नदी के किनारे दुमका एवं कोयल नदी के किनारे पलामू (मेदिनीनगर) अवस्थित है।

झारखण्ड राज्य के उक्त शहर के किनारे बसे हुए हैं। निकायों को नमामि गंगे परियोजना के तहत वर्तमान में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं इंटरसेप्शन डायवर्सन योजना के तहत नहीं शामिल किया गया है। इसलिए राज्य सरकार की यह मांग है कि उपरोक्त नदियों के किनारे बसे हुए, शहरों यथा-रांची, जमशेदपुर, बोकारो (चास), देवघर, गिरिडीह दुमका एवं पलामू (मेदिनीनगर) को भी नमामि गंगे योजना के तहत एसटीपी एवं आईटी नेटवर्क के साथ-साथ आईएलडब्ल्यूएम के लिए भी

स्वीकृति देने की कार्यवाही की जाये। रांची और प्रमुख शहरों में शहरी यातायात को और सुगम बनाये जाने हेतु इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के अधिष्ठापन में केंद्र के सहयोग की अपेक्षा राज्य सरकार को है। मंत्री ने लिखा है कि समर्पित राज्य शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र का समर्थन झारखण्ड में समेकित नगरीय विकास को नयी उड़ान दे सकता है। आशा है कि राज्य के नगरीय परिवेश की और बेहतर बनाने में आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

आपातकाल के 50 साल

ईदिरा गांधी के जिस इमरजेंसी निजाम के अब पचास साल हो रहे हैं, उसकी एक प्रमुख निशानी बेशक उन कुख्यात इक्कीस महीनों में प्रेस का दमन और उसकी स्वतंत्रता का छीना जाना थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार और अब तक अंतिम बार भी, बाकायदा एक सेंसरशिप तंत्र खड़ा किया गया था, जिसका काम हर छपने वाले शब्द को छपने से पहले जांचना था, ताकि तमाम प्रकाशित सामग्री का शासन को इच्छा के अनुकूल होना सुनिश्चित किया जा सके। याद रहे कि यह वह जमाना था जब जन माध्यम या मास मीडिया का दायरा, पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित था। रेडियो जरूर तब तक एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका था, लेकिन वह पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में था और एकदम शुरूआती दौर का टीवी भी। सिनेमा जरूर एक और स्वतंत्र माध्यम था और सभी जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान उसे भी नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गयी थी। यह सब, खासतौर पर अपने तौर-तरीके में, देश के लिए तब तक पूरी तरह से अपरिचित ही था। की तस्वीर है। लेकिन, यह सोचना सही नहीं होगा कि इमरजेंसी के दौर में प्रेस जो कर रही थी, उसकी यह प्रतिनिधि तस्वीर थी। बेशक, इमरजेंसी में प्रेस की स्वतंत्रता पर भीषण हमला हुआ था। इमरजेंसी के दौरान बेशक, पत्र-पत्रिकाओं में क्या छप सकता है, उसे बाकायदा सेंसर किया जा रहा था। खाली छोड़ा जाना या काले रंग से रंगकर प्रस्तुत किए जाना, प्रतिरोध की एक शानदार कहानी कहता था। इसके और प्रखर हिस्से के तौर पर अनेक अखबारों तथा पत्रिकाओं ने, शुरू के दिनों में पूरे-पूरे पन्ने खाली या काले कर के छोड़ दिए थे। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के एक काले धब्बे की तरह है जिसने आवाम के अधिकार को ध्वस्त किया था और लोकतंत्र पर हमला कर उसे खंडित भी।



मेघ : सुबह-सुबह की महत्वपूर्ण घड़िके बाद दिन-भर उजसाह रहेगा। किसी लाभदायक कार्य के लिए व्यवहारक स्थितियां पैदा होगी। अल्प-परिश्रम से ही लाभ होगा। कामकाज में आ रहा अक्रोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। घरेलू बहुभूत्य वस्तुओं के क्रय का योग है। शुभांक-1-5-7

वृष : परामर्श व परिस्थिति सभी का सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग से आपकी निकटता बढ़ेगी। व्यावसायिक उपक्रम में उलटफेर की शुरुआत हो सकती है। स्थाई सम्पति के निर्माण, मरम्मत व पुनर्स्थापना पर व्यय भार बढ़ेगा। किसी की टीका-टिप्पणी से आपको परेशानी हो सकती हैं। शुभांक-2-5-6

मिश्रुन : विश्वस्त लोगों के कहे अनुसार चलें। राजकीय कार्यों में सतर्कता बरतें। मान-सम्मान को ठेस लग सकती है। जोश से कम व होश में रहकर कार्य करें। नये आगंतुकों से लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। परिवार के साथ मनोरंजनिक स्थल की यात्रा होगी। शुभांक-5-7-9

कर्क : पुरानी पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। परिश्रम प्रयास से कार्य सफल होगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। बुरी संगति से बचें। नौकरी में समाधानीपूर्वक कार्य करें। अपनों का सहयोग मिलेगा। पत्नी व संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी। मनोरथ सिद्ध का योग है। शुभांक-1-3-6

सिंह : दाम्पत्य जीवन में तनाव का वातावरण बन सकता हैं। शारीरिक सुख के लिए व्यसनों

संस्थापक

स्व. डॉ अभय कुमार सिंह

स्वामित्व वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए

मुद्रक, प्रकाशक

मंजू सिंह

द्वारा निरौंदी, बोडैया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रधान संपादक

सौरभ कुमार सिंह

संपादक

अविनाश ठाकुर*

फोन : 95708-48433

पिन:- 834006

e-mail

khabarmantra.city@gmail.com

R.N.J No.

JHAHIN/2013/51797

धनबाद कार्यालय

लुवी सर्कुलर रोड, धनबाद 826001 से प्रकाशित।

(R.N.J No. आवेदित)

*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।

चाहे वह बोर्डरूम हो या युद्धभूमि – मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त महिलाएँ ही बदलाव की वाहक होती हैं; महिलाओं के लिए अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे विकसित करना अत्यंत आवश्यक है, और योग इसकी कुंजी है। योग की जन्मस्थली भारत में आज भी इस प्राचीन जीवनशैली को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के पोषण के लिए एक दार्शनिक पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। भगवद्गीता (अध्याय 2, श्लोक 50) में कहा गया है- योग: कर्मसु कौशल, अर्थात योग कर्मों में कौशल है।

भगवान श्रीकृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि- सच्चा योग शारीरिक आसन या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात में परिलक्षित होता है कि हम अपने दैनिक कर्तव्यों को कितनी कुशलता और ध्यानपूर्वक निभाते हैं।

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि योग में परिवर्तनकारी क्षमता है, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों के पोषण में, जो हमारे समाज की नींव हैं।माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग ने वैश्विक मंच पर एक कल्याणकारी और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में पहचान प्राप्त की है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जो भारत की महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक मान्यता सिद्ध करता है।इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम,एक धरती, एक स्वास्थ्य के लिए योगहू है ' जो कि योग की सर्वसमावेशी और सार्वभौमिक अपील को रेखांकित करती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि योग किसी कंपीराइट, पेटेंट या रॉयल्टी से मुक्त है। यह लचीला है – आप इसे अकेले, समूह में, गुरु से या स्वयं भी सीख सकते हैं। जैसे-जैसे हमारा राष्ट्र विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि योग को महिलाओं और बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए।

भारत की कुल आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या लाभगर्ह दो-तिहाई है, और वे स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। अतः उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है, और योग की

मजबूत बनाता है। विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं की विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार योग एक समग्र और प्रभावी समाधान प्रदान करता है। योग को अपनाकर महिलाएँ गर्भावस्था से पूर्व और बाद के परिवर्तनशील समय की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनती हैं। प्रसव पूर्व योग, अपने विशेष आसनों और ध्यान तकनीकों के साथ, गर्भावस्था की परेशानियों को कम करता है, दर्द प्रबंधन में सहायता करता है, और ऊर्जा को बढ़ाता है। यह गर्भवती माताओं को शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रसव के लिए तैयार करता है। प्रसवोत्तर योग, स्तनपान कराने वाली माताओं को उनकी रिकवरी, भावनात्मक सहायता, स्तनपान को बढ़ावा देने और माँ-बच्चे के रिश्ते को मजबूत करने

में मदद करता है। महिलाओं में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए, भारत में 25 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक सशक्त नेटवर्क है, जो योग को महिलाओं और बच्चों को



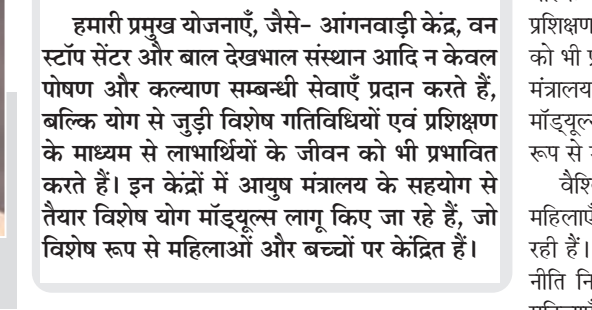
(लेखक देश के प्रसिद्ध डॉक्टर एवं भाजपा के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट है) इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को 50 वर्ष होने को है लेकिन आज भी लोकतंत्र के उस काले अध्याय को याद करना आवश्यक है। स्वातंत्र के बाद से ही देश को अपनी जागीर मात्र समझने वाला गांधी परिवार अपने आप संविधान से भी ऊपर समझता आया है। 50 वर्ष बाद भी आपातकाल प्रासंगिक है क्योंकि विपक्षी दल आज भी उसी मानसिकता का शिकार है। भारतीय लोकतंत्र पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किए गए सबसे बड़े आघात को इसलिए याद रखना भी आवश्यक है क्योंकि इसके पीछे के विचार की छाप आज भी कांग्रेस हाइकमान और कांग्रेस शासित सरकारों के निर्णयों में दिखाई देती है।

केन्द्र में सत्तारूढ़ दल पर संविधान को खतरे में डालने के आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद संविधान की हत्या की सबसे बड़ी दोषी है। अगर कांग्रेस संविधान के लिए इतनी प्रतिबद्ध है तो तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करती कि इंदिरा गांधी ने अपनी संसद सदस्यता खारिज किए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए आपातकाल लगाया था और इस क्रम में इसी संविधान को कुचला और उसकी प्रस्तावना को मनमाने तरीके से बदल दिया। आज को पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि आपातकाल के दौरान, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विभिन्न राजनैतिक विरोधियों, समाजसेवी और पत्रकारों को गिरफ्तार कर

ए वाउंडेड सिविलाइजेशन में आपातकाल के संदर्भ में लिखा है कि रभारत एक लंबे समय से दोहरी सच्चाई के साथ जी रहा था, एक और आजाद भारत की गुंजती आवाजे थी तो दूसरी ओर अब भी अस्वतंत्र, सत्ता का गुलामी झेलता एक असंगठित समाज। आपातकाल ने उस छिपी



हमारी प्रमुख योजनाएँ, जैसे- आंगनवाड़ी केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और बाल देखभाल संस्थान आदि न केवल पोषण और कल्याण सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करते हैं, बल्कि योग से जुड़ी विशेष गतिविधियों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इन केंद्रों में आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार विशेष योग मॉड्यूल्स लागू किए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर केन्द्रित हैं।



के दैनिक जीवन में अपनाने के लिए जानकारी, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर रहा हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की वकालत की है। वे कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक का यह अनुमान है कि महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि से भारत के औद्योगिक उत्पादन में 9% तक की वृद्धि हो सकती है और 2047 तक हम एक उच्च आय वाले विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह सब तभी हासिल किया जा सकता है जब हमारे पास शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ महिला कार्यबल हो। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, बच्चे भी जीवनशैली संबंधी विकारों, स्त्रीन

नहीं भुलाया जा सकता आपातकाल



चरमरा चुकी हैं, कानून मौन, संसद दिशाहीन और प्रेस निशब्द है। लोकतंत्र का जो ढांचा वर्षों से खड़ा किया गया था, वह एक झटके में अतीत की मनमानी और निरंकुशता की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। यह कोई अस्थायी राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि हमारे गणराज्य की आत्मा

आपातकाल झेला है। ऐसे कई प्रकरण हालिया वर्षों में ही नजर आते हैं जब कांग्रेस ने उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को न सिर्फ दबा दिया बल्कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर दी। यूपीए सरकार में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था, यह कांग्रेस के तानाशाही रवैये का

पर निर्भरता और शैक्षणिक दबावों से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं।

योग इन चुनौतियों के लिए साक्ष्य-आधारित, समयबद्ध और सांस्कृतिक रूप से निहित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह एकाग्रता, याददाश्त बढ़ाने, भावनात्मक विनियमन, नींद की गुणवत्ता और तनाव के प्रबंधन को बेहतर करता है - जो समग्र बचपन के विकास के प्रमुख घटक हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से, हमारा मंत्रालय योग को बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास में शामिल कर रहा है, जो आजीवन स्वास्थ्यवर्धक आदतों की नींव रख रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत योग को महिलाओं और बच्चों के जीवन के अभिन्न अंग के रूप में अपनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

हमारी प्रमुख योजनाएँ, जैसे- आंगनवाड़ी केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और बाल देखभाल संस्थान आदि न केवल पोषण और कल्याण सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करते हैं, बल्कि योग से जुड़ी विशेष गतिविधियों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इन केंद्रों में आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार विशेष योग मॉड्यूल्स लागू किए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर केन्द्रित हैं। वैश्विक व्यवस्था के बदलते विमर्श में, महिलाएँ हर मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आईटी से लेकर अंतरिक्ष तक और नीति निर्माण से लेकर सामरिक रक्षा तक, महिलाएँ नई अग्रिम पंक्ति की योद्धा हैं।

हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नेतृत्व इसका जीवंत उदाहरण हैं। यह स्पष्ट है कि मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त महिलाएँ असाधारण परिवर्तनकारी शक्ति बन सकती हैं-और योग उनकी इस अपार क्षमता का आधार है। योग के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महिला और बाल विकास की अपनी नीतियों में योग को सक्रिय रूप से शामिल करके, हम अपनी सांस्कृतिक संप्रभुता पर जोर दे रहे हैं। योग को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक सहभागी अभियान, एक जन-आंदोलन के रूप में देखा जाना चाहिए (केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि-कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अधुण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जिस तरह इंदिरा गांधी ने मैं ही देश हूँ की भावना से लोकतंत्र को कुचल दिया था, वैसे ही आज भी कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से गांधी परिवार, संगठन और राष्ट्र को अपने निजी हितों के अधीन देखना चाहता है। लोकसभा चुनावों में बार-बार जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व आत्ममंथन के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दोषारोपण करता है। कांग्रेस शासित राज्यों में आज भी हम वही तानाशाही चरित्र देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रेस को धमकाया गया और कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया गया। यह सब उस विचारधारा का विस्तार है जो आपातकाल के दौरान अंकुरित हुई थी, कि सत्ता एक विशेष परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार है और कोई भी असहमति देशद्रोह मानी जाएगी।

पिछले वर्ष आपातकाल की वर्षगांठ पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौन प्रस्ताव लेकर आए, तो कांग्रेस उसके विरुद्ध खड़ी हो गई और हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस आपातकाल को सही मानती है और यह चाहती है कि लोकतंत्र को कलंकित करने और संविधान का निरादर करने वाले इस तानाशाही भरे कदम की निंदा तक नहीं की जानी चाहिए।

आपातकाल की बात केवल इतिहास की गलियों में गुम होने वाली घटना नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक जीवित स्मृति है कि जब संस्थाएं कमजोर और जनता मौन होती है, तो कैसे एक चुनी हुई सरकार भी लोकतंत्र को कुचल सकती है। इस स्मृति को जीवित रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि लोकतंत्र स्वतः नहीं बचता, उसे हर दिन पुनः अर्जित करना होता है। ताकि जब कोई राजनीतिक दल, कोई नेता या कोई परिवार संविधान से ऊपर उठने की कोशिश करे, तो जनता एक स्वर में कह सके नहीं, हम वह भूल नहीं सकते!

आपातकाल की बात केवल इतिहास की गलियों में गुम होने वाली घटना नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक जीवित स्मृति है कि जब संस्थाएं कमजोर और जनता मौन होती है, तो कैसे एक चुनी हुई सरकार भी लोकतंत्र को कुचल सकती है। इस स्मृति को जीवित रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि लोकतंत्र स्वतः नहीं बचता, उसे हर दिन पुनः अर्जित करना होता है। ताकि जब कोई राजनीतिक दल, कोई नेता या कोई परिवार संविधान से ऊपर उठने की कोशिश करे, तो जनता एक स्वर में कह सके नहीं, हम वह भूल नहीं सकते!

आपातकाल की बात केवल इतिहास की गलियों में गुम होने वाली घटना नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक जीवित स्मृति है कि जब संस्थाएं कमजोर और जनता मौन होती है, तो कैसे एक चुनी हुई सरकार भी लोकतंत्र को कुचल सकती है। इस स्मृति को जीवित रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि लोकतंत्र स्वतः नहीं बचता, उसे हर दिन पुनः अर्जित करना होता है। ताकि जब कोई राजनीतिक दल, कोई नेता या कोई परिवार संविधान से ऊपर उठने की कोशिश करे, तो जनता एक स्वर में कह सके नहीं, हम वह भूल नहीं सकते!



